making PSUs; and

(c) whether Government would consider introducing special incentives to NRIs/overseas investors willing to invest in loss-making PSUs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA) (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

District Rural Development Agencies

1144. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether State Government have been asked to restructure the district rural development agencies and make them function under the overall supervision, control and guidance of the Zila Parishads;

(b) If so, the details of such instructions;

(c) whether Government propose to monitor such instructions by calling progress reports every month from State Governments; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI VILAS BABURAO MUTTEMWAR): (a) Yes, Sir.

(b) States have been advised that DRDAs should function under the overall supervision, control and guidance of Zilla Parishads. Chairman of Zilla Parishad would be ex-officio Chairman of the Governing Body of DRDA and would preside over its Meetings. Chief Executive Officer of Zilla Parishad would be Member Secretary of the Governing Body of the DRDA. District Collectors/ DMs/Dcputy Commissions arc to be designated as Chief Executive Officer/ Executive Director of Zilla Parishad and will preside over the Meetings of the Executive Committee of the DRDA. Provision has also been made for inclusion of Ex.MPs/MLA.s/Member of Minority Community in the Governing Body of the DRDA.

(c) and (d) States have been requested to restructure the DRDAs in consonance with the revised guidelines and report action taken in the matter. Their response is awaited.

शयनयानों में अनधिकृतए व्यक्तियों द्वारा यात्रा किया जाना

1145. **श्री नागमणि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे को शयनयानो में बिना शयनयान की टिकट वाले अनधिकृत व्यक्तियों को यात्रा न करने देने के संबंध में निदेश जारी किए हैं;

(ख)यदि हां, तो रेलवे ने यह संनिश्चित करने के लिए क्यश कदम उठाए हैं कि ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति शयनयानो में यात्रा न करें; और

(ग)रेलवे के उन कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी, जो जान-बूझकर शयनयानों में अनधिकृत व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति देते हैं?

रेलद मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) एक याचिका पर निर्णय देते समय, राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग ने आदेश दिया कि रेलों को गैर-गलियारेदार शयनयान के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिउ कि ऐसे प्रत्येकए सवारी डिब्बे में यात्रा के लिए वैध द्वितीय श्रेणी शयनयान टिकट धारकों के अलावा किसी यात्री को इन सवारी डिब्बों में न तो प्रवेश करने दिया जाए और न ही डिब्बों के अन्दर रहने दिया जाए, एक चल टिकट परीक्षक/परिचारक तैनात करना चाहिए;

(ख)इस विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार, रेलों को शयनयान दर्जा सवारी डिब्बो में चल टिकट परीक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे, आरक्षित सवारी डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए 20 जोड़ी गाडियों में त्वरित कार्रवाई दल लगाए गए हैं, लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षकोंए की व्यवस्था

(भी की जा रही हैं, इसके अलावा अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए निम्नलिखितउ कदमए उठाए गए हैं:-

(i)लम्बी दूरी के मेल/एक्सप्रेस गाड़ियो के आरक्षित सवारी डिब्बो में मासिक सीजन टिकट धारकों सहित छोटी दूरी वाले यात्रियों के यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं;

(ii)रे0 रा0 पु0 /रे0सु0 ब0 की सहायता से अचानक जांच की जाती हैं और रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनाधिकृत यात्रियों को गाड़ी से उतारने तथा उन पर जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाईण् की जाती हैं;

(iii)आरक्षित सवारी डिब्बों में कर्मचारियों की तैनाती में सुधार लाने के लिए टिकट जांच कर्मचारियोंए के रिक्त स्थानों को भरा जा रहा हैं;

(iv)शयनयान दर्जे में दूसरे दर्जे के टिकट सहितए यात्रा करते पाए गए यात्रियों का ऊंचें दर्जे में यात्रा करते हुए माना जाता हैं और उन पर यथा निर्धारित जुर्माना किया जाता हैं;

(ग)कर्मचारियों की मिली भारत के सिद्ध पाये जाने वाले मामलों में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाईण् की जाती हैं;

Proposal to Close ET&T

1146. SHRI E. BALANANDAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government arc considering to close down the ET&T Corporation due to heavy loss;

(b) what arc the total losses during the last five years including 1994-95 and what action Government have taken to arrest loss trend and for the revival of the Company;

(c) whether it is also a fact that Government have constituted an enquiry into ET&T affairs and allegations against CMD and other senior Management officials; and

(d) if so, what arc the findings of the enquiry and what action Government have taken against CMD & other officials responsible?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) No. Sir.

(b) The profit and loss position of ET&T Limited during the last five years is as under:

(Rs. in lakhs]

	90-91	91-92	92-93	93-94	94-93
Profit	—	7.51	—	—	—
Loss	685.11	'	441.44	622.2	1242.22 (Provisional]

For revival of the Company. ET&T Ltd. has submitted the restructuring plan for consideration/approval of the Government.

(c) and (d) Yes, Sir. A Fact Finding Board of Enquiry was appointed to investigate into the specific complaints received from Members of Parliament and associations against the management of ET&T Limited. Based on the report of the Fact Finding Board, it has beer decided to take disciplinary action agains the then CMD, ET&T and other erran officials of ET&T Limited. Accordingly charge-sheet has been issued to the there